

पटना में दिनांक-05 जून, 2018 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम-16 के अंतर्गत उप नियम-2 (ii) में संशोधन के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्य के निवासी हो और बिहार राज्य में पदस्थापित हो और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान रु० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) से बढ़ाकर रु० 11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये) तथा उनके अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1960 के विनियम-4 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | सुश्री वन्दना सिन्हा, सहायक अभियंता (असैनिक) आई.डी.-5088, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, पटना को अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवाच्युति करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पथों के शोध विकास एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु बिहार सड़क शोध संस्थान (Bihar Road Research Institute) की स्थापना हेतु स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | LPA No.-2285/2016 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 एवं दिनांक 16.05.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-7381 (एस), दिनांक 12.09.2016 को संशोधित करने एवं तदर्थ सहायक अभियंताओं को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

वित्त विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में ERP की सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना स्कीम के तहत 16 करोड़ रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। 7. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

8. पंचायत स्तर पर Common Service Centre को NOFN/Bharatnet के साथ Integrate कर सेवाएँ प्रदान किये जाने हेतु दो वर्षों के अवधि के लिए कुल प्राक्कलित राशि ₹43,68,00,000.00 (तीतालीस करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त एवं कार्यरत सभी प्रकार के कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत रू० 4,00,000/- (चार लाख) रूपये मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में। 9. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

10. बिहार विधान परिषद सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 के संबंध में। 10. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

11. बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 के संबंध में। 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत कर, उपभोक्ता शुल्क अथवा दण्ड/अधिभार लगाने साथ ही Street Light को Public Purpose घोषित करने की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

14. लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन-सह-पुस्तकालय, सिताब दियारा, सारण की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 03 (तीन मात्र) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 14. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

15. सी.सी.टी.एन.एस. योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत राशि ₹7420.47 लाख (चौहत्तर करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार रू०) मात्र को पुनरीक्षित करते हुये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹6455.22 लाख (छौंसठ करोड़ पचपन लाख बाईस हजार रू०) मात्र एवं Gap Funding (अंतर राशि) के रूप में राज्यांश राशि ₹20631.59297 लाख (दो सौ छः करोड़ इकतीस लाख उनसठ हजार दो सौ संतानवे रू०) मात्र अर्थात् कुल लागत राशि ₹27086.81297 लाख (दो सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख इक्कासी हजार दो सौ संतानवे रू०) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. गया जिलान्तर्गत वजीरगंज अंचल के मौजा-इटवां, थाना सं०-545, खाता नं०-169, खेसरा नं०-106, कुल रकबा-10.00 एकड़ भू-हदबन्दी अन्तर्गत अधिशेष अर्जित भूमि दो लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता की नयी डेयरी स्थापना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
16. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

17. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुंगेर की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु पीठासीन पदाधिकारी (वेतनमान 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010) का 1 पद, आशुलिपिक (वेतन स्तर 4) का 1 पद, निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) का 1 पद एवं कार्यालय परिचारी (वेतन स्तर 1) का 2 पद, कुल 5 (पाँच) पद सृजित करने के संबंध में।
17. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

18. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार "प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2018" की स्वीकृति के संबंध में।
18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. श्री राजेश प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, शेरघाटी वर्तमान में अपर मुंसिफ, मधेपुरा (सम्प्रति निलंबित) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त (Dismissal) करने के संबंध में।
19. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

20. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रब्बी विपणन मौसम 2018-19 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (05, अप्रैल, 2018 से 30, जून 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर स्वीकृत कुल 2,500.00 करोड़ रुपये (दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपये) बैंक गारंटी की राशि में से 500.00 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी का उपयोग रब्बी विपणन मौसम, 2018-19 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु करने की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

21. पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन (ई०आर०एम०) योजना के व्यय हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में निर्धारित ए०आई०बी०पी० शीर्ष/विपत्र कोड के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य योजना अन्तर्गत शीर्ष/विपत्र कोड से व्यय भारित करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।
21. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

22. त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए दिनांक 08.07.2018 को मतदान सम्पन्न कराने एवं इस हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।
22. स्वीकृत।

वित्त विभाग

23. प्रबंधक (बिहार शिक्षा सेवा, वर्ग-2) मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के लिए दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन स्तर-6 के स्थान पर वेतन स्तर-9 की स्वीकृति के संबंध में।
23. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवम् 09 बालिका मदरसों अर्थात् कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु 2,15,00,00,000/- (दो अरब पंद्रह करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवम् विमुक्ति के संबंध में।
24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत खोले जाने वाले 54 नये ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की निधि से खोले जाने वाले 10 अन्य ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों अर्थात् कुल 64 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक, प्रति संस्थान 13 विभिन्न पद अर्थात् कुल 832 (आठ सौ बत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।
25. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत खोले जाने वाले 23 नये जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की निधि से खोले जाने वाले 10 अन्य जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों अर्थात् कुल 33 जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्य हेतु प्रति संस्थान 13 विभिन्न पद अर्थात् कुल 429 (चार सौ उन्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।
26. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

27. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत पद के अन्तर्गत नियोजित माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹11,07,50,00,000/- (ग्यारह अरब सात करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।
27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28. याचिका संख्या-18887/2008 एवं एल.पी.ए. संख्या-1754/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु रामकरण ठाकुर बालिका उच्च विद्यालय ईमनसराय, प्रखंड-पटोरी, जिला-समस्तीपुर को वर्ष 1984-85 चरण के नवसृजित विद्यालय के रूप में स्थापित/संचालित करने हेतु विद्यालय के लिए दिनांक-01.01.1989 के प्रभाव से 01 (एक) प्रधानाध्यापक, 08 (आठ) सहायक शिक्षक, 01 (एक) लिपिक एवं 02 (दो) परिचारी के पदों के सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा मान्यता की स्वीकृति एवं उनके वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।
28. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

29. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08.2012 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रभावी तिथि एवं पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा अवधि (Qualifying Service period) में संशोधन के संबंध में।
29. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

30. ₹61.57 करोड़ (एकसठ करोड़ सतावन लाख) की लागत पर शास्त्रीनगर, पटना में प्रस्तावित 330 चतुर्थवर्गीय टाईप 'ए' स्टाफ क्वार्टर, दो अदद गार्ड रूम एवं परिसर विकास सहित आवास निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
30. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

31. ₹443.62 करोड़ (चार सौ तेतालीस करोड़ बासठ लाख) की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में प्रस्तावित आवासीय परिसर में पदाधिकारियों के आवासन हेतु 752 Units के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 31. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

32. ₹249.90 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ नब्बे लाख) की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में प्रस्तावित आवासीय परिसर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के आवासन हेतु Type 'B' के तहत 752 यूनिट के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 32. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

33. ₹120.43 करोड़ (एक सौ बीस करोड़ तैंतालीस लाख) की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में प्रस्तावित आवासीय परिसर में तृतीय श्रेणी के कर्मियों के आवासन हेतु Plot B-1 Type 'A' 432 Units के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 33. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

34. ₹52.76 करोड़ (बावन करोड़ छिहत्तर लाख) की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में प्रस्तावित आवासीय परिसर में माननीय मंत्री आवासन (G+1) 20 Units, Annexe Block (G+2)—20 Units, Security Post-20 Units, Barrack (G+1), Club House (G+1) एवं Staff Convenience Block के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 34. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

35. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसा के अन्तर्गत 205 मदरसा एवम् 609 मदरसा में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में देय नियत वेतन के लिये अनुदान की राशि 60,00,00,000/—(साठ करोड़) रुपये की स्वीकृति एवम् विमुक्ति के संबंध में। 35. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

36. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332+199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1,50,00,00,000/—(एक अरब पचास करोड़) रुपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष 1,15,00,00,000/—(एक अरब पन्द्रह करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। 36. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

37. वित्तीय वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान) अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम से ₹50,00,00,00,000/- (पचास अरब रूपये) की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं प्रथम तिमाही के वेतनादि के भुगतान हेतु ₹18,61,35,03,000/- (अठारह अरब एकसठ करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार रूपये) की व्यय की विमुक्ति।
37. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

38. राजभवन, पटना में डॉ० पुष्पलता पाटिल पुस्तकालय, अभिलेखागार एवं मुख्य भवन के प्रथम तल पर स्थित पुस्तकालय तथा गेस्ट हाउस के रख-रखाव हेतु पुस्तकाध्यक्ष का एक (01), सहायक पुस्तकाध्यक्ष का एक (01), परिचारी (आदेशपाल) का एक (01), परिचारी (दफ्तरी) का एक (01), परिचारी (कुक) का दो (02) तथा परिचारी (रूम वेयरर) का दो (02) कुल 8 (आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
38. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

39. "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" तथा इस योजना को खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य में लागू करने हेतु स्वीकृति के संबंध में।
39. स्वीकृत।